मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की, वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राजस्व में बढ़ोतरी के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए।

‘सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने यह भी कहा कि अनियमितता पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी

- **मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में मानसून में क्षतिग्रस्त सड़कों का ड्रोन सर्वे कराकर 20 अक्टूबर से पहले मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिये।**

जयपुर, 28 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क, बायपास, आरओबी और आरयूबी जैसी जनउपयोगी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग पाए जाने और अकारण देरी पर कॉन्ट्रेक्टर के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उनसे वसूली की जाएगी। साथ ही, अनियमितता पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होगी।

मुख्यमंत्री शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का ड्रोन सर्वे करवाकर 20 अक्टूबर से पहले मरम्मत कार्य पूरा करवाया जाए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग को बेहतर सड़क निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की सूची संधारित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व में बढ़ोतरी के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सड़क, बायपास आदि के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण पर उन नीतियों पर विचार करें जिसमें विभाग को भविष्य में राजस्व की बढ़ोतरी हो। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय प्रोजेक्ट्स एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

‘मैंने कभी नहीं कहा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार में सब कुछ आरएसएस तय करता है? ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि लक्ष्य वही है, जो हमारे देश की भलाई है। उन्होंने सरकार के साथ संघ के समन्वय पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ मौजूदा सरकार ही नहीं, बल्कि हर सरकार के साथ हमारा अच्छा समन्वय है...कहीं कोई झगड़ा नहीं है। आगे जब उनसे पूछा गया कि भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों का संघ साथ क्यों नहीं देता, तो जवाब में आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अच्छे काम के लिए जो हमसे सहायता मांगते हैं हम उन्हें सहायता देते हैं। हम सहायता करने जाते हैं तो जो दूर भागते हैं, उन्हें सहायता नहीं मिलती तो हम क्या करें। आपको सिर्फ एक पार्टी दिखती है जिसको हम सहायता कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी देश चलाने के लिए या पार्टी का कोई काम चलाने के लिए अगर वो अच्छा है तो हमारे स्वयं सेवक जाकर मदद करते हैं...हमें कोई परहेज नहीं है। सारा समाज हमारा है। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। उधर से रुकावट है तो हम उनकी इच्छा का सम्मान करके रूक जाते हैं।

आरएसएस ने विभाजन का विरोध नहीं किया, इस सवाल का जवाब देते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि यह गलत जानकारी है। संघ ने विभाजन का विरोध किया था, लेकिन उस समय संघ के पास क्या ताकत थी। अखंड भारत एक सच्चाई है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के विभाजन को रोकने में संघ की भूमिका को समझना हो तो हो शेषाद्रि की पुस्तक “ट्रैजिक स्टोरी ऑफ़ पार्टीशन” पढ़नी चाहिए।

बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय

चर्चा है कि जेडीयू 102, भाजपा 101, चिराग पासवान 20, मांझी व उपेन्द्र कुशवाह 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे

- **कहा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा तो लगभग तय हो गया है, पर कौन सी पार्टी किस सीट से लड़ेगी, इस पर चिंतन जारी है।**

पटना, 28 अगस्त। बिहार में इस साल (2025) होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर अब तक की सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो गया है। सीटें भी बंट गई हैं। सबसे पहले यह जान लें कि एनडीए में पांच दल हैं। बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी एवं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है। इन्हीं पांच दलों में सीटों का बंटवारा फाइनल हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लड़ेगी। बिहार की 243 सीटों में जेडीयू को 102 सीटें दी गई हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (रामविलास) को 20 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटें दी जाएंगी। एक-दो सीटें आगे-पीछे हो सकती हैं।

हालांकि इस आंकड़े को लेकर आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत जल्द घोषणा होगी। बिहार में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग की तस्वीर अब काफी साफ हो गई है।

लेकिन कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी इसका मंथन आगे होगा। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली गए थे। इस बीच अब सीटों का ये आंकड़ा आया है। जेडीयू को अधिक सीटें देकर यह बताने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है।

जयपुर महिलाओं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महिलाओं के सर्वेक्षण के आधार पर, राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 65 प्रतिशत रखा गया है, तथा शहरों को इस मानक से काफी ऊपर, ऊपर, पर, नीचे या काफी नीचे श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

कोहिमा और अन्य शीर्ष रैंक वाले शहर मजबूत लैंगिक समानता, नागरिक भागीदारी, पुलिस व्यवस्था और महिला-अनुकूल बुनियादी ढ ांचे से जुड़े थे।

दूसरी ओर, पटना और जयपुर जैसे शहरों का प्रदर्शन कमजोर संस्थागत प्रतिक्रिया, पितृसत्तात्मक मानदंडों और शहरी बुनियादी ढ ांचे में अंतराल के कारण खराब रहा।

रिपोर्ट में कहा गया है, ''कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर, मुंबई राष्ट्रीय सुरक्षा रैंकिंग में सबसे आगे हैं, जो अक्सर उच्च लिंग समानता, बुनियादी ढ ांचे, पुलिसिंग या नागरिक भागीदारी से संबंधित है, जबकि रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटना और जयपुर ने सबसे कम स्कोर किया है, जो खराब बुनियादी ढ ांचे, पितृसत्तात्मक मानदंडों या कमजोर संस्थागत जवाबदेही से संबंधित है।''

छत्तीसगढ़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

2000 से अधिक लोगों का अस्थायी रूप से पुनर्वासित किया गया है। शिविरों में रहने, खाने और सोने की संपूर्ण व्यवस्था की गई है।

अमेरिकी वीज़ा की अवधि घटाई जाएगी?

वाशिंगटन, 28 अगस्त। अमेरिकी प्रशासन अपने वीज़ा नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है और अगर ये नियम स्वीक़त हो जाते हैं तो इससे अमेरिका में रह रहे वीजा धारकों की समयावधि घट जाएगी। इससे वहां रह रहे लोगों खासकर छात्रों को अपने देश जल्द वापस लौटना पड़ सकता है।

अमेरिकी गृह विभाग ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि ये प्रस्तावित नियम अगर स्वीकार हो जाते हैं तो इससे वीज़ा के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा और शासन की इन व्यक्तियों की जांच और निगरानी करने की क्षमता बढ़ेगी। यह नियम कुछ ही तरह की वीज़ा श्रेणी पर लागू होगा और इस श्रेणी में विदेशी छात्रों को मिलने वाला वीज़ा भी शामिल है। अमेरिका के गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, “बहुत लंबे समय से, पिछले प्रशासनों ने विदेशी छात्रों और अन्य वीज़ा धारकों को लगभग अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की अनुमति दी है, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा होता है।” विदित हो कि सन 1978 से, यहां आने वाले विदेशी छात्रों को एफ श्रेणी का वीज़ा एक खास अवधि के लिए दिया जाता रहा है। अन्य वीज़ा श्रेणी से भिन्न यह वीज़ा धारकों को बिना किसी अतिरिक्त जांच-पड़ताल के अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की अनुमति देता है। अब अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि विदेशी छात्रों ने अमेरिकी उदारता का लाभ उठाया है और वे ऐसे “स्थायी” छात्र बन गए हैं, जो अमेरिका में रहने के लिए उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में स्थायी रूप से खुद का नामांकन किए रहते हैं।

- **अगर ऐसा हुआ तो वहां काम या पढ़ाई के लिए गए लोगों को जल्दी ही लौटना पड़ सकता है।**

बिहार में घुसे तीन संदिग्धों पर 50 हजार का इनाम घोषित

तीनों पाकिस्तानी संदिग्ध नेपाल की सीमा से बिहार में घुसे हैं राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है

- **इस घटनाक्रम के बाद राहुल की वोट अधिकार यात्रा में भी बदलाव किया गया है अब वे खुली जीप की बजाय बंदगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं।**

मोतिहारी, 28 अगस्त। बिहार में नेपाल के रास्ते तीन संदिग्ध लोगों के घुसने के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

इस संबंध में मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आज यहां कहा है कि एजेंसियों की ओर से इनपुट जारी किया गया है और उसी इनपुट पर काम करते हुये हम लोग लगातार हाई- एलर्ट पर हैं। सीमावर्ती इलाकों में लगातार जांच की जा रही है। साथ ही पूरे जिला पुलिस को भी अलर्ट किया गया है।

उन्होंने बताया कि तीनों संदिग्ध लोगों पर 50 हजार रुपये इनाम की घोषणा की गयी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आम जनता से अपील की गयी है कि अगर ये तीनों संदिग्ध कहीं दिखाई देते हैं तो नजदीकी थाने, डायल 112 या संबंधित पुलिस अधीक्षक के सरकारी मोबाइल या बेस नंबर पर फोन कर सूचना दे सकते हैं।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तीन संदिग्ध नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। इनमें हसनैन अली (रावलपिंडी निवासी), आदिल हुसैन (उमरकोट निवासी) और मोहम्मद उस्मान (बहावलपुर निवासी) के नाम शामिल हैं। पुलिस की ओर से इन तीनों संदिग्धों के नाम, तस्वीर सार्वजनिक कर दिये गये हैं।

पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों को खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है।

वहीं मोतिहारी पुलिस ने तीनों आतंकियों पर 50 हजार रुपए इनाम की घोषणा की है। बिहार में घुसे तीनों आतंकियों का पासपोर्ट भी सामने आया है। बताया जाता है कि तीनों आतंकी मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर से बिहार में घुसे हैं।

खबर है कि तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते ही काठमांडू पहुंच गए थे। वहां से पिछले सप्ताह बिहार में घुसे हैं। खुफिया इनपुट के आधार पर आशंका है कि आतंकियों का मकसद बिहार में किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आतंकी अलर्ट के बाद राहुल गांधी की यात्रा में बदलाव किया गया है। सीतामढ़ी में वे जिस कैंप में रुके थे वहां से सीधे जानकी मंदिर पहुंचे। यहां कई जगहों पर स्वागत मंच बनाए गए थे, लेकिन राहुल वहां नहीं रुके।

मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी का रोड शो भी था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया है। राहुल गांधी अब ओपन जीप की जगह बंद गाड़ी से चल रहे हैं।

दिनेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और इन आरोपों के चलते दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था। यह तनाव इस हद तक पहुंचा कि दोनों देशों ने अपने-अपने देशों में तैनात राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था।

मोदी जापान और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देशों के प्रमुख से होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर मैं 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। हम इस यात्रा के दौरान अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान देंगे। यह यात्रा हमारे सभ्यतागत बंधनों और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का भी अवसर होगी जो हमारे लोगों को परस्पर जोड़ते हैं।(पीएम ने कहा कि जापान से मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाऊंगा। भारत एससीओ का सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है। सात साल में चीन की अपनी पहली यात्रा के दौरान पीएम दुनिया की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ नजदीकी बढ़ाकर मेक इन इंडिया पहल के लिए समर्थन जुटाएंगे।

‘वैश्विक नेताओं से निजी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **इसके लिए भारत पर हर तरफ से दबाव डाला जा रहा है। कभी टैरिफ बढ़ाकर कभी एच वन-बी वीज़ा के नाम पर तो कभी ऑपरेशन सिंदूर व सीज़फायर पर दावे करके तो कभी रुस -यूक्रेन जंग को मोदी की जंग बताकर।**
- **प्र.मंत्री मोदी ने भी इस दबाव को स्वीकार किया और कहा कि हम पर दबाव बढ़ सकता है, हम उसे सहन करेंगे पर हम किसानों, पशुपालकों व लघु उद्योगों के हितों से समझौता नहीं करेंगे।**

तो नवैरो ने दोहराया: “मेरा मतलब मोदी की जंग है, क्योंकि शांति का रास्ता आंशिक रूप से दिल्ली से होकर गुजरता है... भारत कल ही 25 प्रतिशत की छूट पा सकता है अगर वह रूसी तेल खरीदना बंद कर दे और उनकी युद्ध मशीन को ईंधन देना बंद करे।”

उन्होंने आगे कहा: “इसमें कोई विवाद नहीं है। आप आँकडे देखिए और फिर वे कहते हैं, ‘हम रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे।’ तो इसका क्या मतलब है?”

यह पहली बार नहीं है जब नवैरो ने यूक्रेन में रूस के हमलों के लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया है। करीब 10 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स में एक तीखे लेख में उन्होंने लिखा था: “रूस यूक्रेन पर हमला जारी रखे हुए है, क्योंकि उसे भारत के वित्तीय समर्थन से मदद मिल रही है, और अमेरिका (और यूरोप) के टैक्सदाता यूक्रेन की रक्षा में अरबों डॉलर खर्च करने को मजबूर हैं।”

हालाँकि कई अनुभवी विश्लेषकों का मानना है कि रूसी तेल केवल एक दिखावा है, और वास्तव में अमेरिका को जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, वह है भारत के विशाल बाज़ार तक पहुँच न मिल पाना, जो कि ऊँचे टैरिफ और विभिन्न नौकरशाही संबंधी अड़चनों के चलते संभव नहीं हो पा रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि बाज़ार को उसके उत्पादों के लिए खोले जो कि कोई भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि इसका मतलब होगा भारतीय किसानों की बर्बादी।

एक वरिष्ठ राजनयिक ने जब पूछा गया कि अमेरिका भारत के पीछे क्यों पड़ा है, तो उन्होंने कहा: ये सब अर्थव्यवस्था के कारण है।”

वाइट हाउस के ट्रेज़री सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को इस बात की पुष्टि भी कर दी कि “यह केवल रूसी तेल के बारे में नहीं है।”

बेसेंट ने कहा कि भारत ने व्यापार समझौता वार्ताओं में केवल “दिखावा” किया है।

नवैरो ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “महान नेता” बताया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा, वह इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि वॉशिंगटन की असली चिंता भारत की व्यापारिक बाधाएँ हैं।

नवैरो ने कहा कि वे इस बात से हैरान हैं कि “भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है जहाँ बुद्धिमान लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन वे हमसे आँखों में आँखें डालकर कहते हैं कि ‘हमारे टैरिफ दुनिया में सबसे ऊँचे नहीं हैं’, जबकि सच्चाई यह है कि वे सबसे ऊँचे हैं।”

भारत पर अमेरिकी दबाव का एक और पहलू है - ट्रम्प प्रशासन की एच वन-बी वीज़ा कार्यक्रम को लेकर नाराजगी, जिसका सबसे बड़ा लाभार्थी भारत है।

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने बुधवार को कहा कि ट्रम्प प्रशासन एच वन-बी कार्यक्रम में बदलाव की योजना बना रहा है, जो भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच सबसे लोकप्रिय गैर-प्रवासी वीज़ा है। इसके साथ ही ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में भी बदलाव किए जा सकते हैं।

लुटनिक ने कहा: “मैं एच वन-बी कार्यक्रम को बदलने में शामिल हूँ। हम इस कार्यक्रम को बदलने जा रहे हैं, क्योंकि यह बहुत खराब है।”

ऑपरेशन सिंदूर भी दबाव का बिन्दू है। ट्रम्प ने मंगलवार को फिर भारत के इस दावे का खंडन किया कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि इस झड़प में भारत ने अपने सबसे महंगे राफेल जेट खो दिए।

ट्रम्प के ये बार-बार के दावे सीधे-सीधे उनके मित्र नरेन्द्र मोदी की सरकार की उस स्थिति पर हमला हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी विदेशी सरकार ने सैन्य अभियान रोकने का दबाव नहीं डाला।

प्रधानमंत्री ने स्वयं दबाव को स्वीकार किया। सोमवार को, जब अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ पूरी तरह लागू होने में दो दिन बाकी थे, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार “किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हितों पर समझौता नहीं कर सकती।”

उन्होंने यह भी जोड़ा: हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम उसे सहन करेंगे।

हाईकोर्ट ने वो कर दिखाया जो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य द्वारा जनहित याचिका में 2021 की भर्ती परीक्षा रद्द करने की गुहार करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता आरती सिंह ने कहा कि परीक्षा में 859 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, और गिरफ्तारियों को देखते हुए प्रतीत होता है कि अधिकांश अभ्यर्थियों ने अनुचित व गैर कानूनी माध्यमों से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हो सकते हैं, परन्तु वास्तविकता में कितने अभ्यर्थियों ने गलत रास्ते अपनाए थे, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है।**
- **अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि आर.पी.एस.सी. द्वारा अपनाई जा रही कुप्रथाओं को देखते हुए हाईकोर्ट इन सभी मामलों पर स्वतः संज्ञान ले रहा है, जिस पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की जाएगी।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी भर्ती परीक्षा रद्द करने के पक्ष में थे, परन्तु राज्य सरकार में वरिष्ठ अफसरों का एक गुट था जो पुरजोर तरीके से परीक्षा रद्द नहीं होने देने के पक्ष में था। राज्य सरकार में परीक्षा रद्द करने को लेकर इतनी असमंजता क्यों थी, इस पर कई गाथाऐं, उप-गाथाऐं सुनने में आती है। परन्तु न्यायाधीश समीर जैन ने एस.ओ.जी. की जांच रिपोर्ट, महाधिवक्ता द्वारा दी गई सलाह और ‘केबिनेट कमेटी’ द्वारा दी गई सिफारिश के बल पर 2021 की भर्ती परीक्षा को रद्द कर पुनः आयोजित करने के आदेश दिए हैं।

न्यायाधीश समीर जैन ने अपने आदेश में तत्कालीन आर.पी.एस.सी. अध्यक्ष संजय श्रोतिया समेत अन्य सदस्य, जिनमें बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, मंजू शर्मा, संगीता आर्या और जसवंत राठी पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इन अफसरों ने आर.पी.एस.सी. जैसी संवैधानिक संस्था, जिसे प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को चयन करना होता है, की विश्वसनीयता को छलनी कर दिया, जिससे आमजन का प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओ पर विश्वास टूट सा गया। न्यायाधीश समीर जैन ने हिन्दी के एक मुहावरे ‘घर का भेदी-लंका ढाएं’ का उपयोग करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों को आर.पी.एस.सी. जैसी संस्था के सम्मान को सुदृढ़ रखना था और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता को बचाए रखना था, उन्हीं अफसरों ने इस संस्था और लोगों के हितों से विश्वासघात किया। न्यायाधीश समीर जैन ने कहा कि इन अफसरों ने पेपर लीक गिरोह के साथ खुलकर मिलीभगत की और व्यापक स्तर पर पेपर लीक करवाया, जिससे आमजन का आर.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर से विश्वास उठ सा गया।

अदालत ने अपने आदेश में इस तथ्य को रिकॉर्ड पर लिया कि एस.ओ.जी. द्वारा की गई जांच में सामने आया था कि परीक्षा (13 से 15 सितम्बर 2021) से एक महिने पहले (अगस्त के पहले हफ्ते में) ही परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इस जांच में यह भी सामने आया था कि बाबूलाल कटारा ने सबसे पहले रामूराम रायका को पेपर सौंपा था ताकि वे अपने बच्चों, शोभा और देवेश रायका, को दे सकें। जांच में यह भी सामने आया कि बाबूलाल कटारा ने ही रामूराम रायका को सलाह दी थी कि वे आर.पी.एस.सी. चैयरमेन से मिले ताकि इंटरव्यू में उन्हें अच्छे नम्बर मिल सके। एस.ओ.जी. की जांच में यह भी सामने आया कि तत्कालीन आर.पी.एस.सी. चैयरमेन और अधिकारी परीक्षा पेपर लीक करने की साजिश में शामिल थे, और चैयरमेन के साथ-साथ तत्कालीन राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह, मंजू शर्मा और बाबूलाल कटारा पेपरों को फोटोकॉपी करने और कैमरे से फोटो खींचकर पेपर लीक करने की साजिश में शामिल थे। अदालत ने एस.ओ.जी. द्वारा दी गई चार्जशीट और उसमें दिए गए बयानों में आपने आदेश में अंकित किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि बाबूलाल कटारा तथा उनके साथ कार्यरत अन्य सदस्य उनके पुत्र और अन्य अभ्यर्थियों के लिए पेपर चुराने की साजिश में लिप्त थे और अभ्यर्थियों को ‘इंटरव्यू’ के समय पैसे के लेन-देन के बारे में बात करते थे और यह भी तय करते थे कि किस अभ्यर्थी के कितने मार्क्स बढ़ाये जाएगें।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी अंकित किया कि कई अपराधिक गिरोह, जिनमें कालेर गिरोह और जगदीश विश्नोई गिरोह शामिल हैं, ने 10-10 लाख रुपये में पेपर खरीदे थे। एस.ओ.जी. की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इन दोनों गिरोह के बीच में पहले से कोई भी सम्पर्क या समझौता नहीं था, यानि वे केवल गहलोत सरकार के दौरान खुले आम आर.पी.एस.सी. सदस्यों से मिलकर व्यापक पेपर लीक की वारदातों को अंजाम देने के लिए साथ आए थे। अदालत ने यह भी कहा कि एस.आई. भर्ती परीक्षा-2021 की जांच के दौरान 100 से भी अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है। अदालत का कहना था कि परीक्षा में 859 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, और गिरफ्तारियों को देखते हुए प्रतीत होता है कि हर आठ में से एक अभ्यर्थी ने अनुचित व गैर कानूनी माध्यमों से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हो सकते हैं, परन्तु वास्तविकता में कितने अभ्यर्थियों ने गलत रास्ते अपनाए थे, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। गौरतलब है कि 859 पदों में से करीब 800 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में चयनित होने के बाद नियुक्ति ली थी। इन 800 अभ्यर्थियों में से केवल 70 से 80 ऐसे अभ्यर्थी थे, जो किसी अन्य सरकारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, परन्तु उन्होंने नियुक्तियां नहीं ली थी। यानि केवल 10 प्रतिशत ऐसे चयनित अभ्यर्थी थे, जिन्होंने किसी अन्य सरकारी परीक्षा में भाग लिया था और वहां उत्तीर्ण हुए। अदालत ने इन अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए आदेश दिए हैं कि आर.पी.एस.सी. एस.आई. भर्ती परीक्षा को पुनः आयोजित करने से पूर्व इन सभी उम्मीदवारों को तैयारी करने का उपयुक्त समय दे और सभी तरह के आरक्षणों का भी फायदा दें।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आर.पी.एस.सी. के सदस्यों का अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक करने का आरोप है, जैसे कि, शिक्षक ग्रेड-2 परीक्षा-2022 में जांच के बाद खुलासा हुआ था कि, बाबूलाल कटारा, ने 60 लाख रुपये में एक अभ्यर्थी को पेपर बेचा था, इसके बाद आर.पी.एस.सी. को पेपर कैसिंल करना पड़ा था।

इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा- 2022 और रेवेन्यू अधिकारी ग्रेड-2 भर्ती परीक्षा-2023 में भी एस.ओ.जी. की जांच के बाद सामने आया था कि पेपर लीक किया गया है। गौरतलब है कि रेवेन्यू अधिकारी ग्रेड-2 भर्ती परीक्षा में 1.96 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था। अदालत ने कहा कि आर.पी.एस.सी. द्वारा अपनाई जा रही कुप्रथाओं को देखते हुए हाईकोर्ट इन सभी मामलों पर स्वतः संज्ञान ले रहा है, जिस पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की जाएगी।

भारत ने ट्रंप की ''टैरिफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **पर, यह भी सच है कि, दीर्घकाल की दृष्टि से, भारत की यह सामना करने की नीति लाभकारी ही रहेगी, पर तत्कालिक रुप से आर्थिक पीड़ा जरुर होगी, क्योंकि भारत के अमेरिका को निर्यात होने वाले 45अरब डॉलर के माल पर भारी संकट आयेगा, कुछ रोजगार भी खत्म हो जायेंगे ।**

मांग और घटते लाभ मार्जिन के समय आई है। एसबीआई की एक रिपोर्ट चेतावनी देती है कि भारत का अमेरिका के साथ सरप्लस व्यापार अब घाटे में बदल सकता है, जिससे विकास पर और दबाव पड़ेगा। लेकिन जहाँ यह झटका वास्तविक है, वहीं सरकार की नीतिगत प्रतिक्रिया दीर्घकालिक सोच को दर्शाती है। मोदी के पुशबैक के केंद्र में व्यापारिक निर्भरता का पुनः संतुलन है। चीन के साथ चुनिंदा व्यापार मार्गों को फिर से खोलना, रूस के साथ अवसरों का विस्तार करना, और अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुँच बढ़ाना - इन प्रयासों से भारत किसी एक साझेदार पर निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि यह आत्मनिर्भरता की बात नहीं, बल्कि नीतिगत स्वतंत्रता बनाए रखने का उपाय है। अल्पकाल में, नए बाजार तुरंत नहीं बन सकते, लेकिन दीर्घकाल में, इस तरह की विविधता भारत को अमेरिका के एकतरफा व्यापार निर्णयों की अस्थिरता से सुरक्षित रख सकती है।

पुशबैक का दूसरा स्तंभ है घरेलू बाजार में विश्वास। वर्तमान में खपत भारत की जीडीपी का 61 से अधिक योगदान देती है, और सरकार को भरोसा है कि आंतरिक मांग को प्रोत्साहित कर वह बाहरी झटकों को संतुलित कर सकती है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर घोषित जीएसटी सुधार केवल दो स्लैब 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत इसी दिशा में एक कदम है। यद्यिप इसकी गति पर विवाद है, लेकिन यह सुधार अनुपालन को सरल बनाता है और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दे सकता है। यह भारत के सुधार एजेंडे की निरंतरता को भी दर्शाता है, जिससे निवेशकों को यह भरोसा मिलता है कि बाहरी उथल-पुथल से आंतरिक नीतिगत प्रगति बाधित नहीं होगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में दो उच्चस्तरीय समितियाँ नियामक छूट और संरचनात्मक सुधारों के खाके तैयार कर रही हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद को विकास को मजबूत करने और जीवन स्तर सुधारने के उपाय सुझाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी अर्थशास्त्रियों को विश्वास है कि यदि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे और मौद्रिक नीति अनुकूल बनी रहे, तो वित्त वर्ष 26 में 6.5 प्रतिशत विकास दर हासिल की जा सकती है। ये दोनों पहलू नीति प्रतिक्रिया के दो स्तरों को दर्शाते हैं - एक जो रणनीतिक दृष्टिकोण और संरचनात्मक सुधार प्रदान करता है (गौबा के नेतृत्व वाली समितियाँ), और दूसरा जो समयबद्ध, तथ्यों पर आधारित आर्थिक सलाह देती है यानि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। यह दिखाता है कि भारत बाहरी झटकों के जवाब में दीर्घकालिक योजना और त्वरित आर्थिक सलाह दोनों को सक्रिय रूप से जुटा रहा है।

अल्पकाल में, टैरिफ वृद्धि से नुकसान होगा। श्रम-प्रधान क्षेत्रों के निर्यातकों को दबाव का सामना करना पड़ेगा, और वैकल्पिक बाजार विकसित होने से पहले व्यापार संतुलन बिगड़ सकता है। फिर भी, मोदी सरकार इस अस्थिरता को एक उत्पेरक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है। घरेलू खपत पर दांव लगाकर, सुधारों में तेजी लाकर और वैश्विक साझेदारियों में विविधता लाकर, नई दिल्ली टैरिफ झटके को दीर्घकालिक लाभ में बदलने की रणनीति अपना रही है। हालाँकि इसका लाभ असमान रूप से मिलेगा। अल्पकालिक दर्द टालना संभव नहीं है। लेकिन दीर्घकालिक रूप से इसका लाभ एक अधिक मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था हो सकती है - जो वाशिंगटन की व्यापार नीति की अनिश्चितताओं से कम प्रभावित हो, और अपनी घरेलू मांग व विविध वैश्विक संबंधों पर अधिक आधारित हो।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908